



प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन
गोमतीनगर लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 06 मई, 2022

विषय:- उ०प्र० में डिफेन्स इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत सेन्टर ऑफ एक्सलेन्स के संचालन हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी को वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में यूपीडा के पत्रांक-4484/यूपीडा/डि० का०/961, दिनांक 16.08.2021 एवं 113/यूपीडा-992/डि०कॉरि०/तकनीकी दिनांक 12.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखानुदान के अन्तर्गत अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत धनराशि ₹ 40000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। डिफेन्स इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत स्थापित सेन्टर ऑफ एक्सलेन्स के संचालन हेतु शासन द्वारा स्वीकृति कार्ययोजना के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि में से क्रमशः ₹ 1000.00 लाख एवं ₹ 1000.00 लाख अर्थात् ₹ 2000.00 लाख (रुपये बीस करोड़ मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
2. उक्त धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही किया जायेगा तथा दोनों सेन्टर आफ एक्सीलेन्स के संचालन हेतु शासन द्वारा संस्तुत कार्ययोजना के अनुसार ही दोनों आईआईटी संस्थानों द्वारा व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
3. यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उक्त दोनों प्रौद्योगिकी संस्थानों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. प्रायोजना की आवश्यकताओं एवं औचित्य के आधार पर प्रस्तावित कार्यों का क्रियान्वयन सुसंगत वित्तीय नियमों/विनियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए।
5. धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त आय व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं०. 15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022 दिनांक 30.12.2021 तथा शासनादेश दिनांक 29.03.2022 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370800 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस - वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-3-X-2022-23-दिनांक:5-5-2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 18/2022/77-3099/59/2022/001-549-77-3-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
4. रजिस्ट्रार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
5. उप निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
6. डीन (रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कानपुर एवं वाराणसी ।
8. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
11. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
30प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।